www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े...
3 समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों के निपटान में...
4 यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली बेटी...

वर्ष: 9 अंक: 258 दिल्ली, शनिवार, 12 जुलाई 2025 पृष्ठ संख्या: 4 मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

8 महिलाओं सहित 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

छत्तीसगढ़ (एजेन्सी)। अबूझमाड़ वन क्षेत्र में सक्रिय 37.5 लाख रुपये के इनामी 22 माओवादियों ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुडिया ने बताया कि आज 11 जुलाई को हमने अलग-अलग रैंक के कुल 22 नक्सली कैडर सदस्यों को आत्मसमर्पण कराया है, जिनमें 14 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। इनमें प्रमुख हैं डीवीसी शुकलाल, जो कुतुल एरिया कमेटी के प्रभारी थे और कई सालों से माड़ में मौजूद थे। वह लगभग 17-18 सालों से संगठन में हैं और उन्होंने अपने दम पर कई लोगों की भर्ती की है। रॉबिन्सन गुडिया ने आगे कहा कि अब, इस आत्मसमर्पित कैडर के माध्यम से, हम बाकी समुदाय तक पहुँच रहे हैं। मुख्यधारा के समाज में वापस आने के बाद, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ मिलेगा। इन नक्सलियों पर कुल इनाम 37.5 लाख है। यह सफलता पूरे साल हमारे द्वारा आत्मसमर्पण के लिए अपनाए गए ऑपरेशन और नरम दृष्टिकोण का परिणाम है। माड़ बचाओ अभियान में यह एक उल्लेखनीय सफलता है। माओवादियों ने पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों से 3300 से अधिक लाउडस्पीकर हटाए गए: मुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्र (एजेन्सी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के ठोस प्रयास के तहत राज्य के धार्मिक स्थलों से कुल 3,367 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस ने अकेले मुंबई में ही धार्मिक स्थलों से 1,608 लाउडस्पीकर हटाएं हैं और यह उपलब्धि बिना किसी धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव के हासिल की गई है। उन्होंने कहा, मुंबई अब सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से मुक्त है। फडणवीस ने चेतावनी दी कि सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर दोबारा लगाए जाने पर स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारी जिम्मेदार ठहराये जाएंगे। उन्होंने सदन को सूचित किया, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे। स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस आयुक्त के अधीन उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे। विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कई विधायकों ने यह मामला उठाया था। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने स्थानीय समुदायों पर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव की चिंता जताई, जबकि उनकी सहयोगी विधायक देवयानी फरांडे ने उच्च ध्वनि वाले स्पीकर पर साल भर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

बंगाल में बांग्लादेश के दो मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, नशीले पदार्थ जब्त

पश्चिम बंगाल (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश के दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 10 किलोग्राम गांजा, प्रतिबंधित कफ सिरप की 100 बोतलें और एक चाकू बरामद किया गया। सीमा सुरक्षा बल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि जिले में तराली सीमा चौकी पर बृहस्पतिवार देर रात करीब 1.50 बजे तीन से चार बांग्लादेशी तस्करों के एक गिरोह से मुठभेड़ के दौरान बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। इसमें कहा गया कि सीमा चौकी तराली-1 पर गश्त कर रहे 143 बटालियन के जवानों को आत्मरक्षा के लिए हवा में कई गोलियां चलानी पड़ीं क्योंकि आरोपी जवानों को लगातार चुनौती दे रहे थे। बीएसएफ ने बताया कि गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ लिया गया और पूछताछ के लिए चौकी ले जाया गया जबकि दो फरार हो गए।

दिल्ली को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हमारा संकल्पः सीएम रेखा गुप्ता

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं और सरकार का लक्ष्य है कि इन क्षेत्रों में ठोस नीति और जन-सहभागिता से दिल्ली को देश की सबसे गतिशील सिटी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सपना है कि जब भी कोई विदेशी पर्यटक भारत आए, तो वह दिल्ली देखे बिना वापस न जाए। मुख्यमंत्री दिल्ली पर्यटन विभाग और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित 'DELIGHT for Delhi' समिट में बोल रही थीं। इस आयोजन का उद्देश्य दिल्ली को Driving Experiential Leadership, Innovative Growth and High-Impact Tourism DELIGHT की दृष्टि से एक अग्रणी शहर के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा सहित देश की नामी निवेशक कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति-निर्माता, पर्यटन विशेषज्ञ और उद्यमी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ-साथ देश की आत्मा भी है। यह एक ऐसा शहर है जो समृद्ध संस्कृति, विविध विरासत और गौरवशाली इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज की दिल्ली आधुनिकता और परंपरा का एक अद्वितीय संगम बन चुकी है। भारत मंडपम, यशोभूमि, प्रधानमंत्री संग्रहालय और नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे प्रतिष्ठित स्थल दिल्ली को वैश्विक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री भी देश के पर्यटन विकास को प्राथमिकता देते रहे हैं और हमारी सरकार भी सभी क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के साथ राजधानी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में वह सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो विश्वभर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं, चाहे वह इतिहास, संस्कृति, कला, संगीत, स्वाद या विरासत हो। उन्होंने कहा कि अब आवश्यकता एक प्रभावशाली मंच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतिकरण की है, ताकि दिल्ली की समृद्ध पहचान दुनिया के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि जैसे अन्य राज्यों में पर्यटन का विस्तार हो रहा है, वैसे ही दिल्ली को भी वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत स्थान दिलाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार स्वच्छता, सुंदरता और समग्र विकास के साथ राजधानी की सकारात्मक छवि को मजबूत करने में 24x7 जुटी हुई है, ताकि दुनिया भर से पर्यटक यहां आएं और भारत की संस्कृति व इतिहास का अनुभव कर सकें। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज पर्यटन विभाग और मंत्री कपिल मिश्रा के प्रयासों से इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर से लोगों ने भाग लिया और दिल्ली से जुड़कर भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा सपना है कि जब भी कोई विदेशी पर्यटक भारत आए, तो वह दिल्ली देखे बिना वापस न जाए।

इस अवसर पर पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली अब केवल एक राजधानी भर नहीं बल्कि वैश्विक पर्यटन, सांस्कृतिक समृद्धि और नवाचार के आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह समिट केवल पर्यटन विस्तार का एक कार्यक्रम नहीं बल्कि दिल्ली को वैश्विक निवेश, नवाचार और सांस्कृतिक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों से जोड़ने का एक रणनीतिक मंच है। उन्होंने कहा कि आज हम देश-विदेश से आए अनुभवी प्रतिभागियों से सुझाव लेकर एक मजबूत और व्यावहारिक रोडमैप तैयार कर रहे हैं, जिससे दिल्ली को एक वैश्विक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सके। इस समिट के माध्यम से हमें 8 से 10 ऐसे अहम निर्णय लेने में स्पष्टता और दिशा मिली है जो आने वाले समय में दिल्ली की जनता के हित में होंगे और साथ ही निवेशकों के लिए नए अवसर भी खोलेंगे। दिल्ली, अपनी संस्कृति, विरासत और आधुनिक सुविधाओं के संगम के साथ, निवेश के लिए एक सुरक्षित, लाभदायक और टिकाऊ गंतव्य बनकर उभर रही है। मैं सभी निवेशकों को आमंत्रित करता हूँ कि वे दिल्ली के इस परिवर्तन का हिस्सा बनें।

भारत की धरती का गौरव देश दुनिया में बढा हैः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

संजना भारती संवाददाता/एस रहमान

टोंक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा से जयपुर जाते समय भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में शकुंतलम होटल पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का माला, साफा, स्मृति चिन्ह देकर कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत का मान बढ़ा है। भारत की धरती का गौरव देश-दुनिया में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करने की भूमिका निभा रहा है। आज भारत देश नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारे देश मे लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जिससे जिले व प्रदेश में नए नए विकास कार्य हो रहे हैं।

इस अवसर जिला प्रमुख सरोज बंसल पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराना, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, राजेश शर्मा, प्रधान काबरा, कार्यालय मंत्री ओम प्रकाश पांडे, जिला मंत्री नीलिमा आमेरा, बीना छामुनिया, तरुण टिक्किवाल, रामकिशन गुर्जर, जिला मीडिया प्रभारी कमलेश यादव, आईटी संयोजक लोकेश गुप्ता, प्रवक्ता रत्तीराम पहाड़िया, जुली शर्मा, विजय मालवानी, कार्यालय मंत्री शंभू शर्मा, पंकज पहाड़िया, सह सोशल मीडिया प्रभारी बलवंत मराठा, हेमंत सैनी, आरव सिसोदिया, सुरेश काचरिया, भगवान दास सैनी, लवेश मीणा, देवराज खाटरा, पिंटू बना, राजेंद्र विजय वर्गीय, राजेश मंगल, उत्तम शर्मा शंकर विजयवर्गीय, विजय सिंह, राहुल गुर्जर, अंजली गुप्ता, ममता शर्मा सीमा गौतम, सुभाष सैनी, राजू माहेश्वरी, हेमराज असवार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सीएम नायब सिंह सैनी ने विकास परियोजनाओं में अनाधिकृत अनुबंध वृद्धि पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दिए आदेश

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट पूवार्नुमति के बिना किसी भी विकास कार्य में अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) की राशि बढ़ाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों-चाहे वे विभागीय अधिकारी हों या कंसल्टेंट–के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में गलत एस्टीमेट तैयार करने के कारण वृद्धि होती है, तो ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने वालों को चार्जशीट के साथ साथ अनिवार्य सेवानिवृत्त भी किया जाये। मुख्यमंत्री यहाँ लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से संबंधित कैबिनेट उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में प्रक्रियागत चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि परियोजना में अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो, तो सक्षम प्राधिकारी से इसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में अनाधिकृत वृद्धि न हो सके। उन्होंने विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं के सभी निविदा दस्तावेजों में संपूर्ण संरचनात्मक डिजाइन शामिल हों। इसके अलावा, अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-अनुसूचित मदों (नॉन शेड्यूल आइटम्स) को कम से कम शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए विकास परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अधिकारी ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग अनुराग अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग विनीत गर्ग, आयुक्त एवं सचिव परिवहन टी.एल. सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यशपाल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं वेलनेस एक्सपो का विधान सभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने किया उद्घाटन

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आठवें अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं वेलनेस एक्सपो 2025 एवं 15वीं आरोग्य संगोष्ठी का उद्घाटन किया। नमो गंगे ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय आयोजन (11 से 13 जुलाई 2025) स्वास्थ्य, आयुष, योग, पोषण, फिटनेस, जैविक कृषि, जीवनशैली और समग्र स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञों, संस्थानों, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान कर रहा है।

मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्घाटन वक्तव्य में श्री गुप्ता ने कहा कि भारत के पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय से ही एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और सशक्त समाज का निर्माण संभव है। अध्यक्ष ने कहा कि आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसी भारतीय विधाएं केवल रोगों का उपचार नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णता, आनंद, ऊर्जा और उत्साह से भरने की विधियां हैं। उन्होंने प्राकृतिक जीवनशैली और संतुलित आहार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर को देखना चाहता है, उसे सबसे पहले प्रकृति को अपनाना चाहिए"।

श्री गुप्ता ने नमो गंगे ट्रस्ट के सतत प्रयासों और आयुष मंत्रालय के साथ दशकों से चले आ रहे उनके सहयोग के लिए बधाई दी। उन्होंने योग की गहराई को रेखांकित करते हुए कहा कि योग मात्र शरीर को मोड़ने की कला नहीं, बल्कि चेतना को विस्तार देने की संस्कृति है। उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि शरीर की देखभाल करते समय यह ध्यान रखें कि हम बाइक की सर्विसिंग नहीं करा रहे हैं, बल्कि जीवन के प्रति सचेत, संतुलित और समर्पित होना सीख रहे हैं। उद्घाटन समारोह के उपरांत, माननीय अध्यक्ष ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें आयुष पद्धतियों, पोषण, जैविक खेती, हर्बल उत्पाद, वेलनेस सेवाएं, स्वास्थ्य उपकरण, मेडिसिनल प्लांट्स, इको-फ्रेंडली जीवनशैली वस्तुएं, स्पिरिचुअल हीलिंग, अकादमिक एवं अनुसंधान संस्थान, अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक तकनीकें प्रमुख रूप से प्रदर्शित की गई हैं।

राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला ने चूरु को दिए तीन राष्ट्रीय योगासन कोच

संजना भारती संवाददाता

चूरु। राष्ट्रीय कोच प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025-26 का भव्य समापन 10 जुलाई 2025 को प्रतिष्ठित नेताजी सुभाष चन्द्र बॉस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। 10 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत सहित विदेश के योगासन प्रशिक्षकों को तैयार करने में एक और मिल का पत्थर साबित हुआ यह प्रशिक्षण योगासन को प्रतिस्पर्धा के साथ खेल के रूप में विकसित करते हुए भारतीय संस्कृति व परंपरा को खेल वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने व आगामी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल स्पधाओं के लिए खिलाड़ी तैयार करने के लिए किया गया था।

यह नेशनल कोच प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहल विश्वयोगसना एवं योगासन भारत के माननीय महासचिव व हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य के दूरदर्शी नेतृत्व में आयोजित की गई इस कार्यक्रम में कुल पाँच देश के 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें अकेले चूरु ज़िले से डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया, डॉक्टर सुभाष चन्द सैनी व रामकोरी ढाका सहित कुल 03 कोच शामिल थे।

इस कार्यक्रम का व्यापक लक्ष्य अत्यधिक कुशल और प्रमाणित योगासन कोच का एक कैडर तैयार करना था जो अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दे सकें। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत योगासन के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ योगासन भारत ने इस राष्ट्रीय स्तर के कोच प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपन्न किया और योगासन खेल के पाठ्यक्रम को देश भर के प्रसिद्ध योगाचार्य हुए तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के संकाय सदस्यों के साथ मिलकर तैयार किया गया था जिससे सीखने और अभ्यास के उच्च मानको को सुनिश्चित किया जा सके।

इस कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर सी के मिश्रा, विपिन थापर, संदीप कासनीयाँ, अर्जुन तिवारी, पारुल शर्मा व सरेश मार्कण्डेय भारतीय खेल प्राधिकरण संस्थान के सभी वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया।

चूरु जिले में अब इस कैडर के साथ कुल 06 हो गई है, अब सभी कोच अपनी अपनी जगह लगन एवं कठिन मेहनत से योगासन प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी तैयार करने में जुट चुके हैं जो चूरु, राजस्थान व भारत के लिए मैडल जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

-डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया, जिला अध्यक्ष चूरु योगासन

पंजाब सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में नए सरकारी कॉलेज खोलेगी : हरजोत बैंस

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में नए सरकारी कॉलेज खोलेगी, ताकि शैक्षिक बुनियादी ढांचे को और विस्तार दिया जा सके।

पंजाब विधानसभा में रियात बाहरा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, होशियारपुर विधेयक 2025 और सी.जी.सी. यूनिवर्सिटी, मोहाली विधेयक 2025 पेश करते हुए स बैंस ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही सराहनीय प्रगति को रेखांकित किया और सरकारी कॉलेजों में हुए 85% दाखिला वृद्धि का उल्लेख किया।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में विद्यार्थियों के दाखिले में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जो 2022 में 7 लाख के मुकाबले पिछले शैक्षणिक सत्र में बढ़कर 9 लाख तक पहुंच गई। उन्होंने यह भी बताया कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बठिंडा में दाखिले 1,400 से बढ़कर 2,480 हो गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आई.टी.आई. सीटों की संख्या में लगभग 35,000 की वृद्धि की है और पिछले वर्ष 99% सीटें भर चुकी थीं। इस वर्ष 5,000झ7,000 नई सीटें और जोड़े जाने की योजना है।

इस सफलता का श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में काम कर रही पंजाब सरकार की ह्लराज्य को एक वैश्विक शैक्षिक केंद्र में बदलनेह्न की प्रतिबद्धता को दिया। उल्लेखनीय है कि सरकार अब तक युवाओं को 54,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुकी है, जिससे विदेश पलायन की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगा है।

स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के इतिहास की इकलौती पार्टी है जिसने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान शिक्षा को अपने चुनावी एजेंडे का केन्द्रीय मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा, पंजाब सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी व टूरिज्म और इवेंट मैनेजमेंट जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में नए कोर्स शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई भी छात्र वित्तीय कारणों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महज तीन वर्ष पहले तक कॉलेजों में 90% प्रोफेसर पद रिक्त थे और कुछ फैकल्टी सदस्य 20,000 रुपये मासिक के नाममात्र वेतन पर काम कर रहे थे। मौजूदा सरकार ने उनका मेहनताना बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। उन्होंने सभी गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसरों को यह विश्वास भी दिलाया कि उनकी सेवाओं को महत्व दिया जाएगा और उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। सरकार ने योग्य और प्रतिभाशाली फैकल्टी की भर्ती करके वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरा है।

स बैंस ने आगे कहा कि आज पंजाब अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक पसंदीदा स्थल बन चुका है और वर्तमान में 70 देशों के विद्यार्थी पंजाब में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल और अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच अर्थपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जैसी पहलों को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है।

इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को सीड मनी और मेंटॉरशिप प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी रचनात्मक सोच और व्यापारिक विचारों को विकसित करते हुए नौकरी ढूंढने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें।

सम्पादकीय

भगवंत मान के गैर-जिम्मेदाराना बयान...

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर कटाक्ष करते हुए एक बेहद गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी की है जिसको लेकर विवाद गहरा गया है। देखा जाये तो राजनीति में एक दूसरे की आलोचना करना या विचारों से असहमति जताना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह टिप्पणी देश की विदेश नीति या प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी हो, तब यह सिर्फ आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके राजनयिक प्रभाव भी हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भगवंत मान ने एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह 140 करोड़ लोगों वाले देश में नहीं रहते, बल्कि 10,000 की आबादी वाले देशों का दौरा करते हैं। इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और अपने बयान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की आलोचना वाली टिप्पणी की निंदा करते हुए से "गैरजिम्मेदाराना" करार दिया है। भगवंत मान का नाम लिए बिना मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार राज्य के एक उच्च पदाधिकारी द्वारा की गई उन अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है, जिसमें मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों की अनदेखी की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में राज्य के एक उच्च पदाधिकारी द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां देखी हैं।" उन्होंने भगवंत मान की टिप्पणी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "ये टिप्पणियां गैरजिम्मेदाराना और खेदजनक हैं तथा राज्य के किसी पदाधिकारी को शोभा नहीं देतीं।" जायसवाल ने कहा, "भारत सरकार मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करने वाली ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है।" देखा जाये तो भगवंत मान को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं केवल द्विपक्षीय या बहुपक्षीय बैठकें नहीं होतीं, बल्कि ये भारत की वैश्विक स्थिति, रणनीतिक भागीदारी, निवेश संभावनाओं और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का माध्यम भी होती हैं। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के दौरान दिये गये बयान और घोषणाएं भारत की विदेश नीति का चेहरा बनती हैं। ऐसे में जब देश का एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से इन यात्राओं की खिल्ली उड़ाता है, तो विदेशी सरकारें और कूटनीतिक संस्थान भारत की आंतरिक एकता, राजनीतिक परिपक्वता और स्थायित्व पर सवाल उठा सकते हैं। भगवंत मान को समझना चाहिए कि विदेशी राष्ट्र भारत के भीतर के राजनीतिक मतभेदों को सावधानी से परखते हैं। भगवंत मान जैसे नेताओं की टिप्पणियां यह संकेत दे सकती हैं कि भारत की विदेश नीति पर विपक्षी दलों में विश्वास की कमी है। इससे भारत की राजनयिक विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है, विशेष रूप से तब, जब भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने और जी20 जैसे मंचों पर मुखर भूमिका निभा रहा हो। भगवंत मान को समझना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि नेता राष्ट्रीय मंचों और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर सार्वजनिक बयान देते समय राष्ट्रीय हितों की मर्यादा का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री विदेश में न केवल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि पूरे भारत का भी। ऐसे में उनके प्रयासों का उपहास उड़ाना अंततः देश के सामूहिक सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। विदेशी मीडिया भारतीय नेताओं की ऐसी टिप्पणियों को उद्धृत करता है और कई बार उन्हें संदर्भ से बाहर पेश कर भारत को नुकसान पहुँचाया जाता है। भगवंत मान की टिप्पणी भी इसी श्रेणी में आ सकती है, जिससे भारत की विदेश नीति को लेकर भ्रम फैल सकता है। यह बात निवेशकों, रणनीतिक भागीदारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भारत के प्रति धारणा को भी प्रभावित कर सकती है।

बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

-कमलेश पांडेय

> एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केवल किशनगंज जिले में एक हफ्ते के भीतर निवास प्रमाण पत्र के लिए दो लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कई जगह घर-घर जाकर इंयुमरेशन फॉर्म्स बांट रहे कर्मियों ने लोगों से कहा है कि वे आधारकार्ड की कॉपी ही जमा करा दें। लिहाजा ऐसे कंफ्यूजन से बेहतर है कि आयोग बीच का रास्ता निकाले

बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर पर पक्ष-विपक्ष आमने सामने है और मामला मीडिया माध्यम से आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक पहुंच चुका है। इसलिए उम्मीद है कि देर आयद, दुरुस्त आयद करते हुए न्यायालय ऐसे ठोस दिशा निर्देश जारी करेगा कि भविष्य में राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ से चलने वाले मतदाता सूची सम्बन्धी खेल पर पूर्ण विराम लग सके।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर न केवल आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है, बल्कि ऐसा करने से इसकी प्रक्रिया भी ज्यादा आसान होगी और विभिन्न आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, किसी भी विदेशी व्यक्ति का नाम भी मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, अन्यथा मतदाता सूची की विश्वसनीयता सवालों के कठघरे में रहेगी।

कोर्ट का सही मानना है कि ऐसे एसआईआर अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रह जाए। जहां तक इसे लेकर संशय की स्थिति है तो आधार, राशन कार्ड या जॉब कार्ड को मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से बाहर रखने के कारण बड़ी आबादी के सामने संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सुलगता सवाल है कि जिस आधार पर आप लोगों को सरकारी धनराशि से सहूलियत देते हैं, उसी महत्वपूर्ण 'पहचान आधार' को आप एसआईआर में खारिज कैसे कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जो संस्थागत लूट चल रही है, उसकी अब सोशल ऑडिट जरूरी है, क्योंकि इस मामले में पक्ष-विपक्ष सभी शामिल हैं। सच कहूं तो इससे भारत के उन मूल निवासियों को क्षति हो रही है जिनका देश की सरकार और संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए।

हमारा आशय उस हिन्दू वर्ग से है जो धार्मिक आधार पर राष्ट्र विभाजन के बाद भी राजनीतिक व संवैधानिक षड्यंत्र का शिकार होता आया है। जब पाकिस्तान व बंगलादेश इस्लामीकरण की राह पर बढ़ रहे हैं तो भारत की धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं के साथ बेमानी प्रतीत हो रही है। आलम यह है कि मुस्लिम नेता पाकिस्तान व बंगलादेश से मुसलमानों को बुलाकर यहां बसा रहे हैं और उन्हें सरकारी पहचान पत्र दिलवाने में मदद कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने-टोकने की प्रशासनिक विफलता या मिलीभगत से कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जो हिंदुओं के दूरगामी हित के लिए से चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में एसआईआर की जरूरत है। साथ ही, सरकारी पहचान पत्र बनवाने और उससे लाभान्वित होने के पूरे खेल की समीक्षा हो और जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं और उनके दलों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई हो, कि उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे, राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त हो और अधिकारियों-कर्मचारियों की बर्खास्तगी की जाए। क्योंकि ये लोग भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केवल किशनगंज जिले में एक हफ्ते के भीतर निवास प्रमाण पत्र के लिए दो लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कई जगह घर-घर जाकर इंयुमरेशन फॉर्म्स बांट रहे कर्मियों ने लोगों से कहा है कि वे आधारकार्ड की कॉपी ही जमा करा दें। लिहाजा ऐसे कंफ्यूजन से बेहतर है कि आयोग बीच का रास्ता निकाले।

जहां तक एसआईआर के समय पर सवाल है तो शीर्ष अदालत ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन इसके समय को लेकर जो सवाल उठाया, वह बिल्कुल वाजिब है। ऐसा इसलिए, कि बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। लिहाजा बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह इसका समय भी है। जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं, जहां तक नागरिकता पर फैसला का सवाल है तो बताया गया है कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसा नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है और लोकतंत्र में सबसे अहम है लोक यानी जनता। लेकिन, चुनाव आयोग की मौजूदा प्रक्रिया में जनता को ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। यह रिवीजन जुड़ा है वोटर लिस्ट से, लेकिन मैसेज जा रहा है कि इससे नागरिकता तय होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से राहत मिलेगी कि निर्वाचन आयोग का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि, इतना तो तय है कि इस एसआईआर अभियान का असर अब पूरे देश पर पड़ेगा। ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन जबतक संविधान में अमूलचूल बदलाव नहीं होगा तबतक इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने में मुश्किल आएगी।चूंकि यह मामला केवल बिहार तक सीमित रहने वाला नहीं है। ऐसे में दूसरे राज्यों में वोटर लिस्ट की समीक्षा किस तरह होगी, यह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगला नम्बर पश्चिम बंगाल और असम का आएगा जहां अगले साल चुनाव होंगे। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा स्वरूप तय होता है। इसी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के इस्लामीकरण का यह परोक्ष अभियान निकट भविष्य में थमेगा या जारी रहेगा। क्योंकि इसके तार अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। अमेरिका-पाकिस्तान-चीन दशकों से इस कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि हमारी सरकारें भी अपने वोट बैंक के लिहाज से काम करती आई हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के हिसाब से नहीं। खासकर 15 अगस्त 1947 के बाद उतपन्न अप्रत्याशित स्थिति से!

होना तो यह चाहिए कि भारत सरकार का जनसंख्या रजिस्टर ऑनलाइन हो। उसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि इस ग्राम या मोहल्ले का फलां व्यक्ति अब फलां जगह के लिए पलायन कर गया है। उसका एक जन्म प्रमाण पत्र बने जो पूरे देश में लागू हो। मृत्यु प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बने।सभी दस्तावेज इसी आधार पर बनें और पूरे देश में लागू हों। बैंक भी उसी आधार पर खाता खोलें। आज राशन कार्ड, मजदूर जॉब कार्ड, आधार कार्ड की आड़ में जो संस्थागत लूट चल रही है, वह रूके। लेकिन रोकेगा कौन? जो भ्रष्ट हैं, जांच का जिम्मा उनसे लेकर अन्य को दिया जाए। सोशल ऑडिट से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। डीएम, एसडीएम की ऐसी लापरवाहियों के लिए स्थायी जांच एजेंसी बने। उसकी रिपोर्ट राजनीतिक दांवपेंच से बाहर रहकर लागू करने का प्रावधान बने। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि बिहार में मतदाता पहचान पत्र से जुड़े सुलगते सवालों का जवाब आखिर देगा कौन?

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

अमेरिका ने ब्राजील पर नए टैरिफ लगाकर बढ़ाया तनाव

-नीरज कुमार दुबे

> 2022 में जब वामपंथी नेता लूला ने बोलसेनारो को हराकर सत्ता में वापसी की, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि एक वैचारिक पलटवार भी था। लूला ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने 2023 की शुरूआत में हुई ब्राजील की राजधानी में बोलसेनारो समर्थकों द्वारा लोकतंत्र पर हमले को ट्रंप समर्थित अमेरिकी विद्रोह की तर्ज पर देखा और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की

अमेरिका द्वारा ब्राजील पर नए टैरिफ लगाए जाने के घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति में निजी संबंधों और वैचारिक द्वंद्व की अहमियत को एक बार फिर उजागर कर दिया है। यह व्यापारिक निर्णय उस संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैयर बोलसेनारो के संबंधों तथा वर्तमान ब्राजीली राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की राजनीतिक सोच से जोड़कर देखा जाए। हम आपको बता दें कि तमाम आरोपों का सामना कर रहे बोलसेनारो भागे भागे फिर रहे हैं। ट्रंप ने अपने मित्र का बचाव करने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति से जो आग्रह किया उसे ठुकरा दिया गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति आग बबूला हो गये और टैरिफ लगा दिये।

हम आपको बता दें कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जैयर बोलसेनारो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वैचारिक और व्यक्तिगत संबंध जगजाहिर हैं। दोनों दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं और दोनों ने अपनी-अपनी सरकारों में वैश्वीकरण, पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और वामपंथी आंदोलनों का मुखर विरोध किया। ट्रंप ने बोलसेनारो को "ट्रॉपिकल ट्रंप" तक कहा था और ब्राजील में उनके शासनकाल के दौरान अमेरिका-ब्राजील संबंधों को घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया।

2022 में जब वामपंथी नेता लूला ने बोलसेनारो को हराकर सत्ता में वापसी की, तो यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि एक वैचारिक पलटवार भी था। लूला ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने 2023 की शुरूआत में हुई ब्राजील की राजधानी में बोलसेनारो समर्थकों द्वारा लोकतंत्र पर हमले को ट्रंप समर्थित अमेरिकी विद्रोह की तर्ज पर देखा और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की।

जब अमेरिका की ओर से दबाव आया कि ब्राजील, बोलसेनारो को राजनीतिक या कानूनी संरक्षण दे, तो लूला ने स्पष्ट शब्दों में माफी या विशेष राहत देने से इंकार कर दिया। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने ब्राजील से आयातित स्टील और अन्य उत्पादों पर टैरिफ (शुल्क) बढ़ा दिया। यह कदम औपचारिक रूप से व्यापारिक कारणों से उठाया गया बताया गया, लेकिन समय और संदर्भ को देखते हुए यह एक राजनीतिक दंड जैसा प्रतीत होता है।

देखा जाये तो यह टैरिफ विवाद, दरअसल ट्रंप और लूला के बीच की गहरी वैचारिक खाई का विस्तार है। जहां ट्रंप दुनिया में राष्ट्रवादी और संरक्षणवादी विचारों को बढ़ावा देते हैं, वहीं लूला बहुपक्षीय सहयोग और सामाजिक न्याय के वैश्विक एजेंडे का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्राजील के बीच यह व्यापारिक तनाव केवल आर्थिक न होकर राजनीतिक दबाव की रणनीति का हिस्सा भी बनता है। इस घटनाक्रम से जो महत्वपूर्ण संकेत निकलते हैं वह यह हैं कि व्यक्तिगत रिश्ते अब कूटनीति का नया आयाम बन चुके हैं। साथ ही सरकारों के बीच रिश्ते अब केवल संस्थागत नहीं रहे, नेताओं की वैचारिक संगति या टकराव इन रिश्तों को दिशा दे रही है। इसके अलावा, लूला दक्षिण अमेरिका में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं और वह अमेरिकी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। लूला ने ट्रंप के आग्रह को ठहराते हुए दो टूक कहा था कि ब्राजील के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी नेता का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। यह वक्तव्य न केवल ब्राजील की संप्रभुता के प्रति लूला की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि वह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेंगे।

इसके अलावा, हाल ही में कुछ अमेरिकी और दक्षिणपंथी मीडिया रिपोर्टों में यह चर्चा थी कि ट्रंप प्रशासन से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोलसेनारो के पक्ष में बयानबाजी की और उन्हें "राजनीतिक उत्पीड़न" का शिकार बताया। इस संदर्भ में लूला का कड़ा बयान यह स्पष्ट करता है कि ब्राजील के कानूनी संस्थानों और राजनीतिक प्रक्रिया को बाहरी दबाव में नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि जो व्यक्ति (बोलसेनारो) लोकतंत्र को कमजोर करने का दोषी है, उसे कानून के अनुसार दंड मिलेगा, चाहे उसके समर्थन में कोई भी अंतरराष्ट्रीय नेता क्यों न बोले।

हम आपको बता दें कि बोलसेनारो, जो ब्राजील के दक्षिणपंथी नेता और पूर्व राष्ट्रपति हैं, वह वर्तमान में कई आपराधिक जांचों का सामना कर रहे हैं। उन पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि 2022 के चुनाव में हार के बाद बोलसेनारो ने चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 8 जनवरी 2023 को ब्रासीलिया स्थित संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर उनके समर्थकों ने हिंसक हमला किया, जो अमेरिका में हुई कैपिटल हिल घटना की याद दिलाता है। बोलसेनारो पर इस हमले को भड़काने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की साजिश रचने का आरोप है।

इसके अलावा, एक अन्य आरोप है कि उडश्क्क-19 महामारी के दौरान बोलसेनारो ने वैक्सीनेशन को लेकर गलत जानकारी फैलाई। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने वैक्सीनेशन रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति मिल सके। बोलसेनारो और उनकी पत्नी पर यह आरोप भी लगा है कि उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान सऊदी अरब से मिले बेशकीमती गहनों को निजी संपत्ति मानते हुए ब्राजील से बाहर ले जाने की कोशिश की। इन सभी आरोपों के चलते बोलसेनारो पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। वह कुछ समय तक अमेरिका में शरण लिए हुए थे, जिससे यह संदेश गया कि वह गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। हालांकि अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, परंतु न्यायालय और संघीय जांच एजेंसियां उन पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बहरहाल, अमेरिका द्वारा ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों का प्रतीक हैं। ट्रंप और बोलसेनारो की नजदीकी तथा लूला की वैचारिक दृढ़ता इस संघर्ष को केवल दो राष्ट्रों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संघर्ष बना देती है। आने वाले दिनों में इस बात पर नजर बनी रहेगी कि क्या ब्राजील इस दबाव के सामने झुकेगा या फिर यह टकराव वैश्विक शक्ति-संतुलन को नई दिशा देगा। वैसे यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि ब्राजील अब संप्रभुता, लोकतंत्र और न्याय के मार्ग पर किसी भी प्रकार की बाहरी दखलअंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

कविता

सावन में सजना की याद

ओ सजना सावन में देखो, चलती शीत बयार
नैन तुम्हारे दरश को तरसे, आन मिलो इक बार

हरी-हरी हरियाली झूमे, मेहंदी हाथ सजाई
बूंद-बूंद अंगना में बरसे, उर बजती शहनाई
इक तुम्हरे बिन सूना-सुना लगता है संसार
नैन तुम्हारे दरश को तरसे................

छम-छम नाच रही है पायल, घन घनघोर घटाएं
करती आलिंगन वर्षा का, चंचल हुई लताएं
लोचन हैं मदमस्त निहारे कजरे की ये धार
नैन तुम्हारे दरश को तरसे............

आकुल मन व्याकुल हृदय की व्यथा कही न जाए
नीर नयन में भर-भर जाते प्रिय दरश मिल जाए
बंधी डोर तुमसे जीवन की तुम मेरे आधार
नैन तुम्हारे दरश को तरसे........

-गीता राठौर 'गुंजन'
संगीत शिक्षिका एवं कवयित्री, पूरनपुर, पीलीभीत

जयंती

दुर्गा प्रसाद खत्री

जन्म-12 जुलाई, 1895, वाराणसी; मृत्यु-5 अक्टूबर, 1974) हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक थे। ये ख्याति प्राप्त देवकीनन्दन खत्री के पुत्र थे, जिन्हें भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में भी तिलिस्मी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी।

पुण्यतिथि

विश्वनाथ प्रसाद मिश्र

जन्म-1906, काशी, उत्तर प्रदेश; मृत्यु-12 जुलाई, 1982, काशी) भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक चन्द्रशेखर आजाद के घनिष्ट मित्र थे। ये प्रख्यात साहित्यिक संस्था 'प्रसाद परिषद' के सभापति रहे थे।

कल मिलेंगे

एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था.
मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार कहा-मार दे मुझे डरपोक कहीं के तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है, क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

कीव में रूस ने मचा दी भीषण तबाही, लोग बंकरों में छुपे

(एजेन्सी)।
यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर रूस के भीषण मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में आ गई। रूस ने बुधवार देर रात यूक्रेन पर 700 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इन हमलों से कई इलाकों में 10 लोग घायल हो गए।

कीव के मेयर विताली क्लिचको ने बताया कि शहर में इमारतें, गोदाम, ऑफिस और अन्य गैर-आवासीय ढांचे हमले की चपेट में आए हैं। रूस ने हाल के हफ्तों में यूक्रेनी एयर डिफेंस को पस्त करने के लिए बार-बार डिकोय ड्रोन और मिसाइलों से हमले तेज किए हैं। बीते दो हफ्तों में ये तीसरी बार है जब रूस ने इतना बड़ा हमला किया।

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि यह रूसी आतंक का स्पष्ट विस्तार है। हर रात सैकड़ों शाहिद ड्रोन, लगातार मिसाइल हमले, यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मिशन ने बृहस्पतिवार को बताया कि जून में, युद्ध के दौरान सबसे अधिक नागरिक हताहत हुए, जिसमें 232 लोग मारे गए और 1,343 घायल हुए, जबकि रूस ने पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 10 गुना अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागीं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से 716 बच्चों सहित कम से कम 13,580 नागरिक मारे गए हैं और 34,000 से अधिक घायल हुए हैं।

रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच दो दौर की सीधी शांति वार्ता से लड़ाई रोकने में कोई प्रगति नहीं हुई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि संभावित तीसरे दौर की वार्ता की कोई तारीख तय नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उनके रूसी समकक्ष, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मलेशिया में मुलाकात के बाद अमेरिका और रूस ने शांति वार्ता के लिए नए विचारों का आदान-प्रदान किया है। इससे पहले, कीव के मेयर विताली क्लित्स्को ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि शेवचेनकिव्स्की जिले में एक आवासीय इमारत में आग लग गई और बचावकर्मी राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हैं।

रूस ने हाल में बड़े पैमाने पर हवाई हमले करके यूक्रेनी वायु रक्षा को कमजोर करने की कोशिश की है।

लश्कर और जैश का खतरनाक प्लान, नेपाल के रास्ते भारत पर अटैक की प्लानिंग!

(एजेन्सी)।
नेपाल के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन भारत को निशाना बनाने के लिए नेपाल के रास्ते का फायदा उठा सकते हैं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के राष्ट्रपति के सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने बुधवार (9 जुलाई) को काठमांडू में नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट द्वारा आयोजित एक उच्च-स्तरीय सेमिनार के दौरान ये बातें कहीं। इस सम्मेलन में दक्षिण एशिया में आतंकवाद के ज्वलंत मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए प्रमुख क्षेत्रीय विशेषज्ञ और नीति-निमार्ता एकत्रित हुए।

थापा ने कहा कि भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाएँ अक्सर नेपाल तक पहुँचती हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा होता है। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को लगातार दिए जा रहे समर्थन की भी आलोचना की और इसे सार्क की प्रभावशीलता और व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक बड़ी बाधा बताया। संगोष्ठी में पूरे दक्षिण एशिया में आतंकवाद-रोधी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख सिफारिशों में धन शोधन से निपटने के लिए कड़े कदम, देशों के बीच बेहतर खुफिया जानकारी साझा करना और समन्वित सीमा गश्त - विशेष रूप से भारत-नेपाल सीमा पर - शामिल थीं। वक्ताओं ने सभी क्षेत्रीय हितधारकों से आतंकवाद से निपटने के मामले में दोहरे मापदंड अपनाने से बचने का भी आग्रह किया। भारत के हालिया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया, को सीमा पार आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एक निर्णायक और प्रभावी प्रतिक्रिया के रूप में उद्धृत किया गया। हालाँकि, वक्ताओं ने आईसी-814 अपहरण और पहलगाम घटना जैसी पिछली घटनाओं का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि नेपाल अभी भी असुरक्षित बना हुआ है, जहाँ लश्कर-ए-तैयबा द्वारा आयोजित हमले में एक नेपाली नागरिक सहित 26 नागरिकों की जान चली गई थी।

मंत्रालय ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों को विदेश में अभ्यास की मंजूरी दी

(एजेन्सी)।
खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक इकाई (एमओसी) ने मौजूदा भाला फेंक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाले भारतीय ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा के खिलाड़ियों के पदक की संभावना को बढ़ाने के लिए लंबी अवधि के विदेशी प्रशिक्षण दौरों को मंजूरी दे दी है। भारतीय खिलाड़ी सितंबर में होने वाले विश्व चैंपियनशिप से पहले यूरोप और अमेरिका में अभ्यास करेंगे। एमओसी की 157वीं बैठक में एथलेटिक्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। एथलेटिक्स के लिए 86 लाख रुपये के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा उन खिलाड़ियों के लिए निर्धारित किया गया है जिन्होंने 13 से 21 सितंबर तक तोक्यो में होने वाली प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है।

नीरज चोपड़ा के नाम विश्व चैंपियनशिप के दो पदक है और 27 साल का यह खिलाड़ी एक बार फिर से भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीद होगा। वह 57 दिनों के लिए प्राग और चेक गणराज्य के निम्बार्क में प्रशिक्षण लेंगे। वह शुक्रवार रात अपने फिजियो ईशान मारवाह के साथ रवाना होंगे और पांच सितंबर तक यूरोपीय देश में रहेंगे। इस पूरे प्रशिक्षण का खर्च 19 लाख रुपये आएगा। चोपड़ा ने 2022 में रजत और 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। वह अंजू बॉबी जॉर्ज (2003 में लंबी कूद में कांस्य) के बाद इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पोडियम पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। स्टीपलचेज खिलाड़ी अविनाश साबले, पारुल चौधरी और लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह 15 जुलाई से तीन सितंबर तक कोलोराडो स्प्रिंग्स, लॉस एंजिल्स में प्रशिक्षण लेंगे। सरकार ने तीनों के प्रशिक्षण खर्च के लिए 41.29 लाख रुपये मंजूर किए हैं। ये तीनों राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं और उन्होंने मई में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया था। इसमें साबले ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि चौधरी ने महिलाओं की स्टीपलचेज और 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया था। गुलवीर ने पुरुषों की 10,000 मीटर के साथ-साथ 5,000 मीटर स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था।

खेल मंत्रालय ने मध्यम दूरी के धावक अजय कुमार सरोज को शीर्ष खिलाड़ियों के साथ अभ्यास के लिए 10.32 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था।

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया

(एजेन्सी)।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने ग्राहक को ऋण देते समय भारत में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक पर 4.88 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 'भारतीय रिजर्व बैंक (डिजिटल ऋण) निर्देश, 2025' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एचडीएफसी बैंक पर जुमार्ने के संबंध में आरबीआई ने कहा कि उसने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर और मौखिक रूप से भी स्पष्टीकरण दिया था। आरबीआई ने कहा, मामले के तथ्यों और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिद्ध हो गए हैं और जुर्माना लगाना उचित है।

आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में श्रीराम फाइनेंस का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में उसे कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के जवाब, उसके द्वारा पेश अतिरिक्त स्पष्टीकरण तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने कहा कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सही पाए गए, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है।

आरबीआई ने कहा कि कंपनी ने ऋण भुगतान तीसरे पक्ष के खाते के माध्यम से किया, जबकि ऋण की राशि सीधे कंपनी के खाते में जमा की गयी थी। दोनों मामलों में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि दंड नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।

कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कास्ट करने पर किया रिएक्ट

(एजेन्सी)। अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ को अपनी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी कलाकार हनिया आमिर के साथ काम करने के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब टाइम्स नाउ से बात करते हुए, अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि "कुछ लोगों का वास्तव में अपना एजेंडा होता है"। कंगना रनौत ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में "हर कोई एक हितधारक है"। "मैंने इन लोगों के बारे में काफी कुछ कह दिया है। हमारी बातचीत की शुरूआत में, मैंने बताया था कि हमें राष्ट्र निर्माण की भावना रखनी चाहिए-हर कोई एक हितधारक है। हम ऐसी भावना क्यों नहीं रखते? दिलजीत अपना अलग रास्ता क्यों अपना रहे हैं? किसी और क्रिकेटर का अपना रास्ता क्यों होना चाहिए? यहाँ तक कि एक सैनिक का भी राष्ट्रवाद का अपना रास्ता होता है।" उन्होंने आगे कहा कि "हमें सभी को एक साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए"। उन्होंने कहा, "कोई ऐसा कर रहा है, बेचारा सैनिक राष्ट्रवाद का रास्ता अपना रहा है, बेचारा राजनेता राष्ट्रवाद का रास्ता अपना रहा है। कुछ लोगों का सचमुच अपना एजेंडा है। मैं यह नहीं कह रही कि यह अस्वाभाविक है, लेकिन हमें सभी को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। हमें एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए, और यह तभी होगा जब हम इन राजनेताओं के सामने यह विचार रखेंगे; यह आपका काम है।"

समाधान शिविर में आने वाली शिकायतों के निपटान में गंभीरता दिखाएं अधिकारी: सोनू भट्ट

एडीसी ने समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

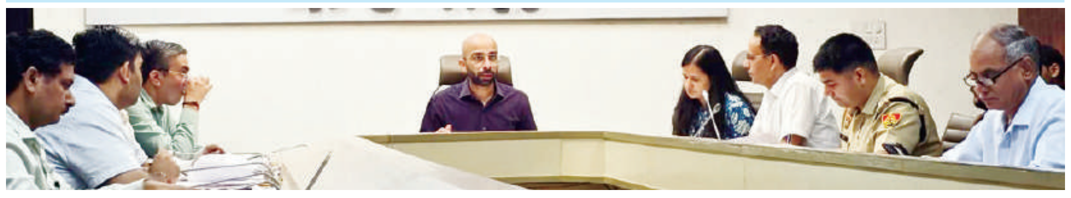

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि समाधान शिविर जनता और शासन के बीच विश्वास की कड़ी है, जिसे बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अधिकारी समाधान शिविर के माध्यम से आई प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका समयबद्ध निवारण करना सुनिश्चित करें।

एडीसी सोनू भट्ट शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में चंडीगढ़ से वीसी के माध्यम से आयोजित समाधान शिविर में आई शिकायतों की समीक्षा बैठक के उपरांत अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों की स्थिति पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट की जाए। समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों का नियमानुसार जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें। एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशन में प्रत्येक सोमवार व वीरवार को प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकार व जिला प्रशासन का ध्येय है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।

इस मौके पर सीटीएम मोनिका, डीडीपीओ संजय टांक, डीएसपी राजीव कुमार तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

डेयरी शिफ्ट न करने वाली 15 डेयरियां जल्द होंगी सील, पशु भी होंगे जब्त: डॉ. वैशाली शर्मा

'चौथे ड्रा में भाग लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई'

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। शहर में अवैध रूप से चल रही पशु डेयरियों को सील करने के लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है। इसके तहत 15 डेयरियों को जल्द ही सील किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि बीते दिनों 21 डेयरी संचालकों को 7 दिन में डेयरी स्थानांतरित करने के नोटिस जारी किए गए थे, जिनकी डेयरी बनकर तैयार थी। इनमें से 6 संचालकों ने अपनी डेयरी को पिंगली डेयरी परियोजना स्थल पर स्थनांतरित कर लिया, परंतु 15 ने डेयरी स्थानांतरण में अपनी रूचि नहीं दिखाई। नोटिस की पालना न करने के चलते अब इन डेयरियों को सील किया जाएगा तथा उनके पशुओं को भी नगर निगम अपने कब्जे में ले लेगा।

नए आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई- उन्होंने कहा कि पिंगली डेयरी परियोजना स्थल पर प्लॉट लेने के लिए पशु डेयरी संचालक 23 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात नगर निगम चौथा ड्रा निकालेगा, जिसके तहत डेयरी प्लॉट आबंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक निगम कार्यालय में 55 आवेदन प्राप्त हो गए हैं।

यह रहेगी आवेदन की प्रक्रिया- उन्होंने बताया कि डेयरी प्लॉट के लिए ड्रा में भाग लेने के लिए डेयरी संचालकों को आवेदन करना होगा। इसके लिए एक प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, 50 हजार रुपये धरोहर राशि, लेट फीस (विलंब शुल्क) 1000 रुपये तथा प्रार्थना पत्र फीस 100 रुपये देने होंगे। प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त राशि की रसीदें लगाकर देनी होंगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए डेयरी संचालक नगर निगम कार्यालय की बेसमेंट में कमरा नम्बर 2 से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

निगमायुक्त ने शहर में अनाधिकृत रूप से डेयरी का व्यवसाय कर रहे लोगों से कहा है कि वे अपनी डेयरियों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। पिंगली स्थित डेयरी स्थल पर प्लॉट हासिल करने के लिए नियमानुसार नगर निगम में आवेदन करें और ड्रा के माध्यम से आबंटित प्लॉटों को हासिल कर उस पर निर्माण शुरू करें। इसी प्रकार जिन डेयरी मालिकों ने प्लॉट अलॉटमेंट के बाद डेयरी निर्माण शुरू नहीं किया है, उनके विरूद्ध भी जल्द ही नगर निगम सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिन्होंने अभी तक प्लॉट की किश्ते नहीं चुकाई हैं, वह भी शीघ्र अति शीघ्र राशि जमा करवा दें, अन्यथा उनके प्लॉट की अलॉटमेंट रद्द करने के साथ-साथ धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

धान की कटाई के लिए कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य: वजीर सिंह

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. वजीर सिंह ने बताया कि राज्य में धान की पराली जलाने की समस्या तथा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा राज्य (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए है। जारी निर्देशों के अनुसार हरियाणा राज्य में धान की कटाई करने के इच्छुक कम्बाईन हार्वेस्टर के मालिक कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाएंगे तथा राज्य में किसी भी कम्पाइन हार्वेस्टर को सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के बिना धान की कटाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कटाई के बाद खुले खेत में धान की पराली जलाना राज्य और उससे सटे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है और इस तरह की हरकतें मिट्टी और पर्यावरण को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रही है।

उन्होंने बताया कि धान की कटाई प्रक्रिया के दौरान जब कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ा जाता है, तो धान के अवशेषों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है, जिससे किसानों को धान के अवशेषों को जलाए बिना अपनी अगली फसल बोने में सुविधा होती है। जिससे किसान आगजनी नहीं करता है और वायु प्रदूषण नहीं होता है। इसलिए धान की कटाई करने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर के मालिक कम्बाईन हार्वेस्टर के गाव सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाना अनिवार्य किया जाऐगा।

उप निर्देशक डॉ. वजीर सिंह ने सभी कम्बाईन हार्वेस्टर मालिको से आग्रह किया है कि वे सभी अपनी कम्बाईन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवा लें ताकि उनको सीजन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंनें सभी किसानो से अपील की है कि वे फसल कटाई के उपरांत बचे हुए अवशेषों में आग न लगाऐ बल्कि इसको पशु चारे के तौर पर या खेत में ही मिलाकर उपयोग करें।

सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, 01.11 करोड़ लोगों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए 1200 करोड़

■ जमुई में प्रभारी मंत्री ने वर्चुअल मोड से आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा, पढ़कर सुनाया मुख्यमंत्री का पैगाम

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 01 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को बढ़े हुए पेंशन राशि का लाभ दिया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 01 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1227.27 करोड़ रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए हस्तांतरित की। पहली बार लाभार्थियों को 400 रुपये के बजाय 1100 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन राशि मिली।

इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि अब हर महीने नामित लोगों को 400 की जगह 1100 रुपए की राशि मिलेगी। यह राशि जून माह से प्रभावी की गई है। हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी के खातों में चली जाएगी। बिहार के सभी विधवा, वृद्ध, दिव्यांग आदि चयनित व्यक्तियों को 1100 रुपए दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि शुक्रवार से इसकी शुरूआत की जा रही है, जो करोड़ों लोगों को फायदा होगा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (35.57 लाख), लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (08.64 लाख), बिहार विकलांगता पेंशन (09.65 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (06.32 लाख), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (01.10 लाख) और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन (49.89 लाख) के तहत वितरित की गई है। यहां बताना जरूरी है कि जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का फैसला लिया था। यह पहली बार है जब पेंशन में इतनी बड़ी वृद्धि हुई है, जिससे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आदि संबंधित जनों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में हर वर्ग को उनका हक और सम्मान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करेगा। इस योजना का वार्षिक खर्च अब 5469 करोड़ से बढ़कर 14678 करोड़ रुपये हो गया है। पेंशन राशि का वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए किया गया। इससे बिचौलियागिरी और देरी की आशंका खत्म हो गई है। समाज कल्याण विभाग ने सुनिश्चित किया है कि राशि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में पहुंचे।

उधर जमुई जिला के शिल्पा विवाह भवन में मुख्यमंत्री के द्वारा पेंशन की बढ़ी हुई राशि के अंतरण कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा ने अग्नि ज्योति प्रज्वलित कर जमुई में निर्धारित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दरम्यान वजीर-ए-आला के पैगाम को पढ़कर आम आवाम तक पहुंचाया। श्री सदा ने कहा कि नीतीश कुमार शासन संभालने के बाद 2005 से लगातार लोकहित में काम कर रहे हैं। अब बिहारी कहलाना गौरव की बात हो गई है। बिहार तेजी से विकास कर रहा है। देश में इस राज्य को कई क्षेत्रों में मानदंड के रूप में देखा जाने लगा है। उन्होंने बढ़ी पेंशन की राशि से जमुई जिला के 01 लाख 90 हजार से ज्यादा लोगों के लाभान्वित होने की जानकारी दी। श्री सदा ने सीएम के पक्ष में गगनभेदी नारे लगाए। सांसद अरुण कुमार भारती, विधायक दामोदर रावत, श्रेयसी सिंह, जिप अध्यक्ष दुलारी देवी, जमुई नप के मुख्य पार्षद मो. हलीम, एडीएम रविकांत सिन्हा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राम दुलार राम, डीपीआरओ वीरेंद्र कुमार, जिला योजना पदाधिकारी भानू प्रकाश, सहायक निदेशक काजोल मोदी, उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार, आइसीडीएस की डीपीओ रश्मि रंजन, बीडीओ अभिनव मिश्रा, सीओ ललिता कुमारी, सीडीपीओ आभा कुमारी, नगर थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, जिला बीस सूत्री उपाध्यक्ष शैलेंद्र महतों, कन्हैया कुमार सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद केशरी, लोजपा रामबिलास जिलाध्यक्ष जीवन सिंह, जिला बीस सूत्री के पूर्व उपाध्यक्ष ई. शंभू शरण समेत भारी संख्या गणमान्य नागरिक और लाभुक इस अवसर पर उपस्थित थे। लाभुक इस बात से बेहद खुश हैं कि 11 जुलाई से उनके एकाउंट में 400 की जगह अब 1100 रुपये आने लगे हैं। इसके लिए वे सभी लाभुक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने घरौंडा और फुरलक में 1 करोड़ 54 लाख के विकास कार्यों की दी सौगात

■ घरौंडा के फुरलक रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य का किया शिलान्यास

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने शुक्रवार को घरौंडा और फुरलक में 1 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भविष्य में हलके के विकास कार्यों में और तेजी आएगी। हलके की तरक्की के काम जारी रहेंगे। सरकार सत्ता को सेवा मानकर विकास करा रही है। उन्होंने कहा कि जिस गति से विकास कार्य हो रहे हैं, उससे 10 साल पहले और आज के घरौंडा शहर में जमीन-आसमान के अंतर को महसूस किया जा सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने घरौंडा के फुरलक रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य का शिलान्यास किया। नगर पालिका की ओर से 1 किमी लंबी सड़क पर 174 लाइट लगवाई जाएंगी। हर लाइट 120 वाट क्षमता की होगी। दोनों साइड ब्रैकेट वाले खंभों की संख्या 87 और ऊंचाई 9 मीटर होगी। इस कार्य पर 85 लाख 74 हजार रुपये खर्च होंगे। उन्होंने दुर्गा कालोनी में 36.02 लाख रुपये की लागत से लगाए जाने वाले ट्यूबवेल का भी शिलान्यास किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से लगाए जाने वाले इस ट्यूबवेल से दुर्गा कॉलोनी, जैल सिंह कालोनी, भट्ठा कालोनी, राजीव कालोनी के लोगों की पेयजल आपूर्ति की मांग पूरी हो सकेगी। नलकूप पर कमरा बनाने, पाइप लाइन बिछाने, गेट व चारदीवारी बनाने आदि का कार्य छह महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने गांव फुरलक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से 26.3 लाख रुपए की लागत से 3 कमरों और पंचायत की ओर से अंबेडकर भवन में 6 लाख रुपये की लागत से बनवाई जाने वाली लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया। घरौंडा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि हलके में अधिकाधिक विकास कार्य हों। दस साल पहले के और आज के घरौंडा में जमीन-आसमान का अंतर है। भविष्य में भी निर्बाध गति से कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि एसएचजी की महिलाओं के लिए घरौंडा में नए प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास महीने भीतर कर लिया जाएगा। सरकार महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है। महिलाएं मजबूत होंगी तो समाज व राष्ट्र भी मजबूत होगा। विश्वास दिलाया कि सेवक के रूप में वे भविष्य में भी कार्य करते रहेंगे।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सोच के साथ कार्य कर रहे हैं कि देश तरक्की करे और लोगों को अधिकाधिक सुविधाएं मिलें। पहले की सरकारें सत्ता को चौधर मानती थी लेकिन वर्तमान सरकार इसे सेवा मानती है। घरौंडा में कालेज, एसडीएम कार्यालय व बस अड्डे की स्थापना, अंडर पास का निर्माण, पुल, आईटीआई, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल व अस्पतालों का उन्नयन जैसे कार्य समाज की भलाई के लिए ही हैं। चालीस से अधिक अवैध कालोनियों को अप्रूव्ड करा कर उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

दस सालों में 80 नई सड़कों और 300 से ज्यादा खेतों के रास्तों को पक्का कराया गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी व रिंग रोड शुरू होने के बाद क्षेत्र में न केवल लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।

करनाल में नई चीनी मिल से पूरे इलाके के किसानों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हलके में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं।

इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता, सचिव रवि प्रकाश शर्मा, पार्षद बलविंद्र सिंहमार, जय नारायण, सेवा पुरूषोतम सेठी, एसडीओ रवींद्र सैनी, पार्षद अनिल जावा, पार्षद अमित गुप्ता, पार्षद अनुज गुप्ता, पार्षद पंकज गुलाटी, महामंत्री सुरेंद्र सैनी, सुरेंद्र जैन आदि मौजूद रहे।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, **'संजना भारती'** को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।

संपर्क करें: दैनिक संजना भारती, समाचार पत्र नई दिल्ली

वाटसेप नम्बर: 9871221635

नागरीप्रचारिणी सभा के स्थापना दिवस पर होंगे विविध आयोजन

प्रेसवार्ता में मीडिया से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल

एसबी संवाददाता

वाराणसी। शुक्रवार को हिन्दी हिन्दी के तीर्थ नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री प्रेसवार्ता में मिडिया से मुखातिब हुए, मिडिया से वार्ता में प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा कि इस वर्ष हिंदी की प्राचीनतम संस्था नागरीप्रचारिणी सभा के वार्षिकोत्सव एवं 132 वें स्थापना दिवस समारोह पर संस्था द्वारा विविध आयोजन किए जायेंगे।

आने वाली 16 जुलाई को इस संस्था का स्थापना दिवस है। 132 बरस पहले, सन 1893 में इसी तारीख को क्वींस कॉलेज के तीन छात्रों–बाबू श्यामसुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह ने इस कालजयी संस्था की स्थापना की थी, इस बार सभा द्वारा 16 से 18 जुलाई-लगातार तीन दिनों तक स्थापना दिवस का समारोह मनाया जायेगा। इस बहुआयामी आयोजन में मूर्धन्य विचारकों के व्याख्यान होंगे और देश के अग्रगण्य संगीतकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे, पुस्तक-प्रदर्शनी और ओपन माइक सेशन भी है। प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा सभा देश भर के हिंदी युवाओं और उनकी सर्जनात्मकता को अवसर और मंच देना चाहती है। इस आयोजन से इसका भी समारंभ होगा। सभी कार्यक्रम हेड पोस्ट ऑफिस; विश्वेश्वरगंज के सामने स्थित नागरीप्रचारिणी सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय में होंगे और ओपन माइक सेशन सभा के ही मुक्ताकाशीय मंच पर होगा। 16 जुलाई की शाम 6 बजे से सुप्रसिद्ध आलोचक और साहित्येतिहासकार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल के व्याख्यान से कार्यक्रम की शुरूआत होगी। पुरुषोत्तम अग्रवाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; नई दिल्ली में भारतीय भाषा केंद्र के प्रमुख और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। उनके व्याख्यान का विषय है सत्यातीत समय में साहित्य व्याख्यान के बाद जाने-माने सितारवादक पूर्वायन चटर्जी की प्रस्तुति होगी। तबले पर श्रुतिशील उद्धव।

17 जुलाई को दोपहर में मुक्ताकाशीय मंच पर युवाओं के लिये ओपन माइक प्रतियोगिता होगी शाम के मुख्य सत्र में प्रखर पत्रकार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी का व्याख्यान है। विषय है दो सौ वर्षों की देहरी पर हिंदी पत्रकारिता का भविष्य। व्याख्यान के बाद मशहूर कवि-नाटककार सुमन केशरी अपने नाटकों हिडिंबा और गांधारी से अंश पाठ करेंगी और तीसरी प्रस्तुति के तौर पर पंडित साजन मिश्र और स्वरांश मिश्र का गायन होगा, जिनके साथ संवादिनी पर वरिष्ठ संगतकार पंडित धर्मनाथ मिश्र और तबले पर अभिषेक मिश्र संगत करेंगे। 18 जुलाई की शाम जाने-माने समाजविज्ञानी और कवि बद्रीनारायण का व्याख्यान बतकही की सामाजिकी पर एकाग्र होगा। तत्पश्चात पं कुमार बोस के स्वतंत्र तबलावादन से कार्यक्रम का समाहार होगा।

इसके अलावा नागरीप्रचारिणी सभा और राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से तीन दिनों तक चलने वाली एक संयुक्त पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें हिंदी के पाठक स्थापना दिवस के अवसर पर मिलने वाली विशेष छूट के साथ अनूठी किताबें खरीद सकेंगे।

सभा के यूट्यूब चैनल पर मुख्य कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इस बीच सभा ने गहरी सूझ और मेहनत के साथ क्लैसिक ग्रंथों के क्रिटिकल एडिशन प्रकाशित किए हैं। जिन्हें बहुत सराहना मिल रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, व्रजरत्न दास द्वारा संपादित अमीर खुसरो की हिंदी कविता, कविता क्या है और पंच परमेश्वर को पाठकों ने हाथों-हाथ लिया है।

प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने कहा सभा सितंबर में हिंदी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक कोश का पुनर्प्रकाशन करेगी। यह प्रकाशन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और सभा के संयुक्त तत्वावधान में होगा।

व्योमेश शुक्ल ने कहा कि सभा के भवन-निर्माण के लिये 5 करोड़ की योजना सभा और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग की ओर से शासन को भेजी गई है।

ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद भव्य उद्घाटन, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम-विधायक डॉ. वाचस्पति

■ रामगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर का विधायक ने फीता काटकर किया उद्घाटन

संजना भारती संवाददाता
मनोज कुमार बिन्द

बारा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को सजाने-संवारने की मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में प्रयागराज जनपद के एक ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य के पूर्ण होने के उपरांत उसका भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस शुभ अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉ. वाचस्पति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

विधायक डॉ. वाचस्पति ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी जनता को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी मजबूती देगी। वर्षों पुराना यह मंदिर जर्जर स्थिति में पहुंच गया था और इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब इसे नई चमक मिली है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पर्यटन विभाग द्वारा विशेष रूप से पूर्वांचल के धार्मिक स्थलों पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रयागराज जैसे तीर्थराज में इस दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और क्षेत्र का विकास हो। विकास खंड शंकरगढ़ में स्थित प्राचीन शिव मंदिर रामगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। परिसर को सुसज्जित करने के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पानी, प्रकाश, साफ-सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर तक जाने वाली सड़कों का भी चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है।

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नंदलाल महंत, ब्लॉक प्रमुख निर्मला देवी, विधायक प्रतिनिधि श्यामू निषाद, फूलचंद पटेल मीडिया प्रभारी नीरज केसरवानी, दिलीप चतुर्वेदी, इंजीनियर प्रकाश सिंह, पुष्पराज सिंह, सुभाष पटेल, राजकुमार पटेल, सचिन सिंह, संदीप पटेल, धर्मराज पाल, राजू द्विवेदी, वीरेंद्र शुक्ला, समरजीत सिंह, दीवान सिंह, विनय सिंह, रत्नाकर सिंह पटेल, अनमोल सिंह, गुड्डू पटेल, विशाल सिंह और ग्राम प्रधान लवकुश समेत सैकड़ों श्रद्धालु व ग्रामीण मौजूद रहे।

कार्यक्रम में भजन-कीर्तन व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर के नवजीवित स्वरूप को देखकर खुशी जताई और सरकार के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने यह भी आग्रह किया कि ऐसे अन्य ऐतिहासिक और उपेक्षित धार्मिक स्थलों को भी चिन्हित कर उनके पुनरुद्धार की योजना बनाई जाए, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सके।

यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली बेटी सिमरन बनी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्त्रोत: मंत्री कृष्ण बेदी

■ मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और सिमरन वाल्मीकि का फूल-मालाओं से किया भव्य स्वागत

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। यूपीएससी की परीक्षा में पलवल जिले की सिमरन वाल्मीकि द्वारा सफलता प्राप्त करने की खुशी में गांच चोचड़ा में शुक्रवार को भव्य स्वागत समारोह व शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर गांव के सरपंच बलदेव वाल्मीकि व समाज के लोगों ने मुख्यातिथि और सिमरन वाल्मीकि का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया तथा पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा बाहर से आए अन्य अतिथियों का भी ग्राम पंचायत द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने सर्वप्रथम यूपीएससी की परीक्षा क्वालीफाई करने वाली सिमरन वाल्मीकि को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि सिमरन वाल्मीकि ने यह सफलता हासिल कर अपने गांव, शहर, प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है और

■ नगर पालिका चेयरपर्सन सुनीता रानी ने मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का किया जोरदार स्वागत

युवा वर्ग विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनी है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को भी इनसे प्रेरणा लेते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और दृढ़ निश्चय व लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान, विद्यार्थियों तथा गांवों व शहर के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खजाने में बहुत बजट है। समूचे प्रदेश के विकास कार्यो के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं। उन्होंने इस भव्य स्वागत कार्यक्रम के लिए गांव के सरपंच की सराहना की।

कार्यक्रम में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली सिमरन वाल्मीकि ने कहा कि इस सफलता को पाने के सफर में उन्हें अपने माता-पिता सहित पूरे परिवारजनों का भरपूर साथ मिला। उन्होंने कहा कि अपनी कड़ी मेहनत और जुनून

के बाद परिजनों के सहयोग ने मुझे कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने संबोधन में बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर के कथन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पियेगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा हासिल कर अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 869वीं रैंक हासिल कर अपने सपनों को साकार करने में सफलता पाई है। बता दें कि सिमरन वाल्मीकि जिला पलवल के गांव अतरचट्टा की रहने वाली है। कार्यक्रम में उनके साथ पिता वीर कुमार व माता स्नेहलता भी मौजूद रही, जिन्हें ग्राम पंचायत व समाज के लोगों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक योगेन्द्र राणा के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे उनके सुपुत्र दक्ष राणा ने भी सिमरन वाल्मीकि को इस सफलता के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस मौके पर डीडीपीओ संजय टांक, सरपंच बलदेव वाल्मीकि, नगर पालिका चेयरपर्सन सुनीता रानी, जिला उपाध्यक्ष संजय राणा, जिला महामंत्री सुभाष चंद व मानवपुरी, राजकुमार मुन्नारेहड़ी, रघुबीर गागट, सुभाष भुम्बक, भाजपा वरिष्ठ नेता सज्जन अत्री, प्रिंसिपल सुरेश शर्मा, पूर्व प्रिंसिपल सुशील वैद, ऋषिपाल बेदी, रणबीर सिंह ढाटरक, अमित राणा, बलराज सिंह, कर्मचंद, दीपक, राकेश, रविन्द्र सहित काफी संख्या में समाज के लोग व ग्रामीण मौजूद रहे।

नशा मुक्ति मुहिम के तहत विद्यार्थियों को नशा ना करने बारे किया गया जागरूक

■ युवा है देश का भविष्य: एसपी आस्था मोदी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। जिला पुलिस द्वारा एसपी आस्था मोदी के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया।

एसपी आस्था मोदी ने बताया शुक्रवार को नशा मुक्ति टीम में शामिल एसआई कर्मबीर, एएसआई ओमप्रकाश, एचसी सुनील कुमार, महिला सिपाही किस्मत, एसपीओ राजपाल तथा एसपीओ प्रदीप कुमार द्वारा जाट स्कूल कैथल, नेशनल स्कूल कैथल, सनराइज स्कूल कुतुबपुर, सरकारी स्कूल कुतुबपुर, रामा स्कूल कुतुबपुर में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की अपील करते हुए बताया कि नशा न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी गंभीर समस्या बनता है। विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करें, पढ़ाई और खेलों में रुचि लें और अपने माता-पिता व गांव का नाम रोशन करें। उन्हें प्रेरित किया गया कि वे खुद तो नशे से दूर रहें ही, साथ ही अपने परिवार व आस-पड़ोस में भी लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें। एसपी ने कहा कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है और यदि वे नशे की चपेट में आए तो समाज व राष्ट्र को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे नशे से खुद को और दूसरों को भी दूर रखेंगे।

इस जागरूकता कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशा मुक्त रहने की शपथ ली और पुलिस टीम का आभार जताया। पुलिस द्वारा आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम गांव-गांव और स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे ताकि युवा वर्ग को नशे के दलदल में फंसने से बचाया जा सके।

डीसी प्रीति ने ली जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक

आपसी तालमेल एवं तत्परता के साथ कार्य करते हुए नशे पर अंकुश लगाएं अधिकारी: डीसी प्रीति

संजना भारती संवाददाता

कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। नशे पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारी आपस में तालमेल और तत्परता के साथ कार्य करें। शहरों के साथ-साथ ग्रामीणों क्षेत्रों में भी गहनता से निगरानी की जाए और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

डीसी प्रीति शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहीं थीं। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए सभी को एकजुटता दिखाने एवं संवाद स्थापित कार्य करने की भी आवश्यकता है। इसको लेकर अधिक से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर बच्चों के साथ नशे के खिलाफ संवाद स्थापित किया जाए। सभी विभागीय अधिकारी व आमजन नशा तस्करी के संदर्भ में जानकारी साझा करे।

डीसी प्रीति ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में संचालित नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का दौरा करते रहे हैं। जिला ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिए कि वे जिले में मेडिकल स्टोर का नियमित औचक निरीक्षण करते रहें और यदि कहीं पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पाई जाती है, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। बैठक में पुलिस विभाग द्वारा नशे के खिलाफ किए जा रहे कार्यों से अवगत करवाया गया। वहीं चिंहित अपराधों पर भी चर्चा हुई।

इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त सुशील कुमार, एचएसवीपी ईओ वकील अहमद, डीएसपी बीरभान, डीएसपी कुलदीप बेनीवाल, जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह, जेल अधीक्षक अशोक कुमार, डीडीपीओ कंवर दमन, जिला उच्च शिक्षा अधिकारी डा. मनोज कुमार, जिला गणित विशेषज्ञ छत्रपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हॉफ मैराथन की तैयारियां पूरी, जन प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री

■ आरकेएसडी कॉलेज में आमजन से मिलेंगे नायब सिंह सैनी ■ डीसी व एसपी ने किया आयोजन स्थल व हॉफ मैराथन रूट का दौरा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। आगामी 13 जुलाई को आयोजित होने वाली हॉफ मैराथन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शुक्रवार सायं डीसी प्रीति व एसपी आस्था मोदी ने मैराथन रूट सहित 12 जुलाई को आयोजित होने वाली बैठकों को लेकर आरकेएसडी कॉलेज का दौरा किया। जहां तैयारियों की समीक्षा करते हुए अंतिम रूप दिया। डीसी ने आमजन का आह्वान किया है कि वे हॉफ मैराथन में बढ़चढ़ कर भाग लें।

डीसी प्रीति व एसपी आस्था मोदी सबसे पहले आरकेएसडी कॉलेज में पहुंचे। जहां उन्होंने प्रिंसिपल कक्ष, मुख्य सभागार कक्ष का दौरा किया। इसके साथ-साथ पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों ने मैराथन रूट का बारीकि से निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान मीडिया से बातचीत में डीसी प्रीति ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी शनिवार 12 जुलाई बाद दोपहर कैथल पहुंचेंगे। जहां वे आरकेएसडी कॉलेज में आमजन

से मिलने के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। इसके साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

रविवार सुबह यानी 13 जुलाई को सुबह पांच बजे हॉफ मैराथन का आयोजन होगा। जिसे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि हॉफ मैराथन को लेकर जिले में विशेष उत्साह बना हुआ है। अब तक भारी संख्या में लोगों ने हॉफ मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। 12 व 13 जुलाई को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्होंने जिलावासियों का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी की नशा विरोधी मुहीम में शामिल होकर ड्रग फ्री हरियाणा मिशन को सफल बनाएं।

एसपी आस्था मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैराथन रूट पर करीब 1500 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरे जिलों से दो डीएसपी की अगुवाई में एक कंपनी अतिरिक्त तौर पर तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा नशा विरोधी मुहीम के तहत पुलिस ने कई गांवों को नशामुक्त घोषित किया है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए लोग हॉफ मैराथन में भाग लेकर ड्रग फ्री हरियाणा के संकल्प को मजबूत करें।

इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, जिला प्रभारी अमरपाल राणा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक गुर्जर, आरकेएसडी कॉलेज के प्रधान अश्वनी शोरेवाला, प्रिंसिपल एसएस मैहला, प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष श्याम बंसल, भाजपा जिला महामंत्री सुरेश संधू, मनीष शर्मा, शैली मुंजाल सहित अन्य पदाधिकारी व अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

डीसी प्रीति ने बताया कि 21 किलोमीटर की हॉफ मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को एक लाख 21 हजार रुपये, द्वितीय को एक लाख रुपये तथा तृतीय को 75 हजार रुपये का नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं 10 किलोमीटर मैराथन में प्रथम विजेता को एक लाख रुपये, द्वितीय को 75 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 50 हजार रुपये की नकद इनाम दिया जाएगा। पांच किलोमीटर की दौड़ रन फॉर फन होगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अलग कैटेगरी बनाई गई है।

पांच किलोमीटर मैराथन: अंबाला रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से शुरू होकर आरकेएम पैलेस तक जाकर वापस विश्राम गृह में समाप्त होगी। (ढाई किलोमीटर एक साइड कुल आना-जाना पांच किलोमीटर)

10 किलोमीटर मैराथन: लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से एचसीटीएम कॉलेज तक जाकर वापस विश्राम गृह में समाप्त होगी। प्रतिभागी को आने-जाने का एक चक्कर लगाना होगा। (एक साइड पांच किलोमीटर, कुल दस किलोमीटर)

21 किलोमीटर मैराथन: लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से एचसीटीएम कालेज तक जाकर वापस विश्राम गृह में समाप्त होगी। प्रतिभागी को आने-जाने के दो चक्कर लगाने होंगे।

जहाँ पेड़ लगते हैं, वहां पुण्य फलते हैं: बी. के. उषा दीदी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। 'जहाँ वृक्ष लगते हैं, वहाँ भविष्य पलते हैं।' इसी संकल्प को साकार करते हुए शिव ज्योतिलिंगम भवन, असंध में एक सुंदर, आध्यात्मिक वातावरण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की विशेषता रही दो आध्यात्मिक व्यक्तित्वों की उपस्थिति-बी. के. उषा दीदी एवं बी. के. सरिता दीदी, जिनके प्रेरणादायक शब्दों ने सभी को प्रकृति के प्रति सम्मान और सुरक्षा का संकल्प दिलाया। उषा दीदी जी ने कहा कि वृक्ष लगाना केवल पर्यावरण सेवा नहीं, बल्कि यह पुण्य कार्य है जो आत्मा के संस्कारों को भी शुद्ध करता है। सरिता दीदी जी ने जोर देकर कहा कि जैसे आत्मा को शक्ति परमात्मा से मिलती है, वैसे ही पृथ्वी को प्राण वृक्षों से मिलते हैं। एक पौधा, एक रक्षक, एक उपकार। सरिता दीदी ने बताया कि यह सेवा केवल एक दिन की नहीं, बल्कि भविष्य की सात्विक पीढ़ी के लिए नींव है। समाप्ति में सभी को वृक्षों की देखरेख का संकल्प दिलवाया गया: एक वृक्ष=एक प्राण=एक सेवा।

कार्यक्रम का वातावरण पूर्णतः सकारात्मक, शांति व प्रेम से युक्त था। हर पौधे को 'प्रभू का बच्चा' मानकर बड़े स्नेह से मिट्टी में रोपा गया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथियों की सहभागिता रही-बी.के. अमनदीप, दर्शन, रूहानी, पवित्रा, उजाला तथा सुभाष, जिन्होंने सामूहिक रूप से पौधारोपण कर प्रकृति के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। सभी ने मिलकर नीम, तुलसी, पीपल, गुलमोहर जैसे औषधीय एवं छायादार पौधे लगाए। अंत में प्रसाद वितरण हुआ, और सभी ने बाबा की याद में प्रकृति को नमन किया।

इस कार्यक्रम ने यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिकता और प्रकृति मिलकर ही धरती को स्वर्ग बना सकती हैं।

राजौंद के वार्ड नंबर 4 सुनारा वाली गली में पानी लीकेज से विभिन्न मकानो में आई गहरी दरारें

पीड़ितों ने सरकार व प्रशासन से मुवावजे की मांग की

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। राजौंद के वार्ड नंबर 4 सुनारा वाली गली में पानी लीकेज से विभिन्न मकानों में गहरी दरार आ गई हैं। सिवरेज पाइपलाइन मेन हाल बैठ गया है। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया कि सिवरेज पाइपलाइन दबाते समय विभाग व ठेकेदार द्वारा घरों के नल के कनेक्शन काट कर दोबारा जोडे थे। वे जोड़ ठीक प्रकार से नहीं लगाए गए थे। उन्हीं कच्चे जोड़ों में से पानी का लगातार रिसाव होता रहा। जिसने आस-पास के कई मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। आरोप लगाया गया कि ठेकेदार ने अपना काम ठीक प्रकार से नहीं किया है।

नागरिक रिंकू वर्मा पुत्र बीरबल वर्मा, नना पुत्र बुधराम, सुनीता, महावीर, निरमल सहित अन्य नागरिकों ने कहा कि मोहल्ले में एक गरीब विधवा स्त्री का कड़ियों का मकान था उसमें दरार आ गई है। एक नागरिक ने एक साल पहले नया मकान बनाया था वह मकान एक ओर चार इंच झुक गया है। एक नागरिक के मकान में 3 इंच की बड़ी व गहरी दरारें आ गई है। पूरे मुहल्ले में दहशत का माहौल है। पिछले

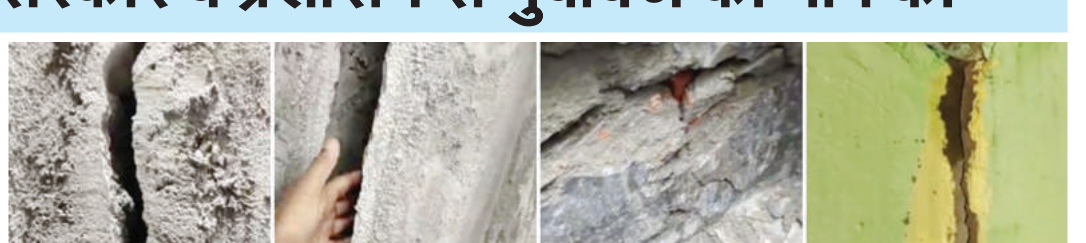

नागरिकों के मकान में आई दरारें।

दिनों गली में सिवरेज पाइप दबाई गई थी सिवरेज का मेन हाल भी धंस गया व उसकी सीमेंट उखड़ गई है। हताश व परेशान नागरिकों ने सरकार व विभाग से ठेकेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उनके मकानों को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है।

मामले के बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जेई हरि सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास मामले की सूचना पहुंच गई है टीम गली में पहुंचकर कनेक्शन को दुरुस्त कर रही है जो सिवरेज मेन होल क्षतिग्रस्त होने की बात आई है मेन हाल को अच्छी प्रकार से दोबारा बनाया जाएगा।

सरकार व प्रशासन से मुआवजे की मांग करते नागरिक। (छाया: एसबी)

जल्द आ सकता है हरियाणा जन विश्वास विधेयक

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा में निवेश का माहौल बढ़ाने और प्रदेश को व्यापार-अनुकूल गंतव्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार की योजना हरियाणा जन विश्वास विधेयक लाने की है। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करने के साथ-साथ नियामक बाधाओं को दूर करना और विभागों में अनुपालन बोझ को कम करना भी है। कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव श्री के.के. पाठक की अध्यक्षता में अनुपालन में कमी और और विनियमन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में हुई बैठक के दौरान इन पहलों की जानकारी दी गई। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार विनियमन को बढ़ावा देकर, छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त और अनुपालन बोझ को कम करके कारोबारी सहुलियत बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव ने आगे कहा कि राज्य सरकार का दृष्टिकोण समग्र है। चाहे औद्योगिक स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करना हो, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो या भवन बिल्डिंग कोड को सरल बनाना हो, हर उपाय का मकसद निवेशकों का भरोसा बढ़ाना और उद्यम को सहायता देना है।

30 व 31 जुलाई को आयोजित होगी हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 का आयोजन 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया जाएगा। इनमें 30 जुलाई को लेवल-3 (पीजीटी) एवं 31 जुलाई को लेवल-2 (टीजीटी) व लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा में प्रदेशभर के 673 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 4,05,377 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे।

इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) तथा शिक्षा बोर्ड की एचटेट परीक्षा की तिथि एक होने के चलते शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा पात्रता परीक्षा-2024 का आयोजन 26 व 27 जुलाई, 2025 के स्थान पर अब 30 व 31 जुलाई, 2025 को करवाया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा 30 जुलाई (बुधवार) को सायंकालीन सत्र में 3:00 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी, जिसमें 399 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 1,20,943 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे।